भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3981
27 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर व्यय

3981. **श्रीमती महुआ माजी:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एसएआईएल, एनएमडीसी, एमईकॉन और बड़ी निजी कंपनियों सहित स्टील क्षेत्र की सभी इकाइयों ने वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान कुल सीएसआर का कितना हिस्सा झारखंड के खनन प्रभावित जनजातीय इलाकों पर खर्च किया, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कई कंपनियां अपने सीएसआर का बड़ा हिस्सा महानगरों, ब्रांडिंग इवेंट्स और अन्य गैर जरूरी मदों पर खर्च करती हैं, जबकि झारखंड के खनन क्षेत्रों के आसपास के गाँवों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी बनी हुई है, और इन क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण गंभीर होता जा रहा है; और

(ग) क्या कंपनियां इन समस्याओं से निपटने के लिए उपाय कर रही हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ग): इस्पात मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) जिनमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड और मेकॉन लिमिटेड शामिल हैं, द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय मुख्यतः इस्पात संयंत्रों, इस्पात टाउनशिप और खदानों के आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है, जहाँ मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग निवास करते हैं, जिसमें झारखंड राज्य भी शामिल है।

सीएसआर पहलें आवश्यकता-आधारित होती हैं और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कौशल विकास, अवसंरचना और आजीविका सृजन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होती हैं। झारखंड के खनन-प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट डेटा केंद्रीय स्तर पर संधारित नहीं किए जाते हैं।

कंपनियों द्वारा सीएसआर पहलें कंपनी अधिनियम, 2013 के सीएसआर प्रावधानों (धारा 135) और सीएसआर दिशानिर्देशों के अनुसार लागू की जाती हैं।

*****